



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 1984/वैशाख 29, 1906  
No. 244] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1984/VAISAKHA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके—

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1984

का०प्रा० 393 (प्र)/18कक/आई डी आर ए/84 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०प्रा० 874(प्र)/18कक/आई डी आर ए/80, तारीख 3 नवम्बर, 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) बिहार राज्य में मैसर्स मोतीपुर शुगर फैक्टरी लिमिटेड, मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 2 नवम्बर, 1982 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, दो वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 769 (प्र)/18कक/उ०वि०वि०प्रा०/82 तारीख 30 अप्रैल, 1982 द्वारा, अवधि को 2 नवम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया था।

और, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तारीख 29 सितम्बर, 1983 के अपने आदेश द्वारा यह निर्देश दिया था कि केन्द्रीय सरकार उक्त औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध ग्रहण करने की अवधि को, 2 नवम्बर, 1983 (वह तारीख जिसको उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने की अवधि को बढ़ाने वाली अधिमूर्चना समाप्त होने वाली थी से परे और नहीं बढ़ाएगी) और आगे यह भी निर्देश दिया था कि उक्त औद्योगिक उपक्रम बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधाधीन तब तक बना रहेगा जब तक कि रिट की प्रार्थना का निपटान नहीं हो जाता।

और, उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख 23 अप्रैल, 1984 के अपने आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह कम्पनी और उसके निदेशकों को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बनाने के लिए युक्तिपूर्ण शरार प्रदान करने के पश्चात्, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने की अवधि को 23 अप्रैल, 1984 से चार सप्ताह के भीतर बढ़ाए।

और, उक्त उच्च न्यायालय द्वारा, यथा निवेशित रूप में कम्पनी और उसके निदेशकों को एक सूचना दी गई है जिसमें प्रबंध ग्रहण की अवधि बढ़ाए जाने के सरकार के आशय को सूचित किया गया है और कम्पनी और उसके निदेशकों को यह कारण बताने का अवसर दिया गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के प्रबंधग्रहण की अवधि को बढ़ाए जाने का आदेश क्यों न किया जाए।

और कम्पनी द्वारा बताए गए कारणों की केन्द्रीय सरकार ने पुष्टि कर दी है।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के प्रबंध के अधीन 31 अक्टूबर, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 अक्टूबर, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे।

[फा०सं० 4(13)/80-सी यू० एस]

९०वी० सरबत, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 19th May, 1984

S.O.393(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 874(E)|18AA|IDRA|80, dated the 3rd November, 1980 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Motipur Sugar Factory Limited, Motipur, District Muzaffarpur in the State of Bihar (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), was taken over under clause (a) of sub-section (i) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of two years upto and inclusive of 2nd November, 1982 and the Bihar State Sugar Corporation Limited, Patna was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, the Central Government by an order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 769(E)|18AA|IDRA|82 dated the 30th October, 1982, extended the period by one year upto and inclusive of the 2nd November, 1983;

And whereas the High Court at Calcutta had, vide its order dated the 29th September, 1983, directed that the Central Government shall not make any further extension of the take over the

management of the said industrial undertaking beyond the 2nd November, 1983, (the date on which the notification extending the period of take over the management of the said industrial undertaking was due to expire), and had further directed that the said industrial undertaking shall continue to be under the management of the Bihar State Sugar Corporation Limited, till the disposal of the writ petition;

And whereas the said High Court has, vide its order dated the 23rd April, 1984, directed the Central Government to extend, after giving the company and its directors a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order, the period of take over the management of the said industrial undertaking under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), within four weeks from the 23rd April, 1984;

And whereas as directed by the said High Court a notice has been given to the company and its directors intimating the Government's intention to extend the period of take over and giving the company and its directors an opportunity to show cause as to why an order of extension of the period of take over of the said industrial undertaking should not be made;

And whereas the cause shown by the company has been considered by the Central Government;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Bihar State Sugar Corporation Limited, Patna for a further period upto and inclusive of the 31st October, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st October, 1984.

[File No. 4(13)|80-Cus]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.